



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2009/भाद्र 16, 1931

No. 502]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2009/BHADRA 16, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 642(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 610क और 610ड के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) और धारा 610ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करना और अधिप्रमाणन) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करना और अधिप्रमाणन) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये नियम 13 सितम्बर, 2009 से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल करना और अधिप्रमाणन) नियम, 2006 के नियम 3 के उप-नियम (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि यदि ऐसे दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क इलेक्ट्रानिक रूप में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एमसीए, जीओवी. इन, के माध्यम से संदत्त किया गया है ऐसे मामलों में, कम्पनी को इलेक्ट्रानिक प्ररूप में उनके प्रस्तुत करने के अतिरिक्त ऐसे दस्तावेजों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु यह और भी कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कतिपय दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के संबंध में जिनमें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल के माध्यम से स्टांप शुल्क का संदाय के अंतर्गत नहीं आते ऐसे दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी क्रमशः एक सौ रुपए

के समतुल्य या उससे कम संदेय है, कम्पनी ऐसे स्थापित पूर्ण दस्तावेजों को सभी संदर्भों में स्कैन करेगी और रजिस्ट्रार द्वारा साक्ष्य के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत करेगी और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी सिवाय उनके जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के अधीन अपराधों को शमन करने के लिए पृथक् रूप में भौतिक प्ररूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा है :

परंतु यह और भी कि कम्पनी सम्यक् रूप से स्थापित ऐसे दस्तावेजों को मूल रूप में ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक रखेगी और सक्षम प्राधिकारी क्रमशः राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या रजिस्ट्रार के स्टांप कलैक्टर होंगे, की मांग पर उन्हें निरीक्षण या सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी”।

[फा. सं. 1/04/2009-सी.एल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 557(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2009

G.S.R. 642(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642 and 610B read with Sections 610A and 610E of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Amendment Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force on the 13th day of September, 2009.

2. In the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006, in rule 3, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that if stamp duty on such documents is paid electronically through Ministry of Corporate Affairs portal [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in), in such case, the company shall not be required to make physical submission of such documents, in addition to their submission in the electronic form :

Provided also that in respect of certain documents filed under the Companies Act, 1956 which are not covered for payment of stamp duty through Ministry of Corporate Affairs portal, and stamp duty payable on such documents in respective state is equal to or less than one hundred rupees, the company shall scan such stamped documents

complete in all respects and shall file electronically for evidencing by the Registrar and shall not be required to submit such documents, except those which are required to be filed for compounding of offences under clause (a) of sub-section (4) of Section 621A of the Companies Act, 1956, in the physical form separately :

Provided also that the company shall retain such documents duly stamped in original for a minimum period of three years from the date of filing of such documents and shall be required to produce the same as and when the same is required for inspection and verification by the competent authority being the Collector of Stamps of respective State or Union Territory or the Registrar”.

[F. No. 1/04/2009-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* number G.S.R. 557(E), dated the 14th September, 2006.